

## चौधरी चरण सिंह, अध्यक्ष— लोक दल द्वारा 26 जून, 1980 को लोकसभा में 1980—81 के बजट पर दिया गया भाषण

चेयरमैन महोदय, वैसे तो हमारे कांग्रेस के जितने भी वजीर हैं, सभी अच्छे और भले आदमी हैं लेकिन हमने, जिस वक्त मंत्रिमंडल की नियुक्ति हुई, तो श्री वेंकटरामन के सम्बंध में तरह-तरह की अच्छी बातें सुनी थीं कि बड़े स्ट्रेट फार्वर्ड हैं, बड़े स्कूपलस हैं। लेकिन बजट को जिस तरीके से उन्होंने पेश किया उससे मालूम होता है कि हमारा पहला अनुमान बिल्कुल निराधार था। मैं यह इसलिए कहता हूँ कि उन्होंने इससे मुद्रा स्फीति या प्रेशरज जो हमारी इकोनॉमी पर डेवलप होंगे, उनको छिपाने की कोशिश की है। सेशन जब शुरू हुआ उसके ठीक दो दिन पहले उन्होंने तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ा दीं और इससे उनको 2100 करोड़ रुपये प्राप्त होने की आशा है। फर्टिलाइजर पर साढ़े पांच सौ रुपये फी टन बढ़ाया। पिछले साल जितना फर्टिलाइजर खर्च हुआ यदि उतना ही होता है तो यह 665 करोड़ रुपया हुआ। ये दोनों मिला कर करीब 2750 करोड़ हो जाता है। हमारी इकोनॉमी के बारे में कहा जाता है कि इसकी कमांडिंग हाइट्स गवर्नमेंट के हाथ में है। प्राइस का बढ़ना, प्राइस का एसकेलेशन और टैक्सेशन इन कनवर्टिबल टर्म्स इंटरचेंजेबल है। साढ़े 27 सौ करोड़ रुपये के टैक्स या इसको आप कुछ भी कह लें, ये सीधे इन्फ्लेशन को बढ़ायेंगे। लेकिन उन्होंने हमें यह समझाने की कोशिश की है कि केवल 1400 करोड़ का ही डिफिसिट है। अब 2750 करोड़, और 1400 करोड़ साढ़े 41 सौ करोड़ यही हो जाता है। इसके अलावा जो रेलवे पैसेंजर्स के लिए इन्क्रीज एनाउंस किया है, रेलमंत्री जी ने किया है, वह 250 करोड़ है जो पहले 200 करोड़ था। 250 करोड़ यह और 44—45 सौ करोड़ वह, यह सब डिफिसिट हुआ। आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी लोन ले रहे हैं। वह आमदनी तो है नहीं, एक लोन ही है। उससे भी मुद्रा स्फीति बढ़ेगी, उससे भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स डेवलप होंगे। लेकिन उसको आप निकाल भी दें, आई एम एफ से जो लोन आप ले रहे हैं, करीब पांच सौ करोड़, उसको आप निकाल भी दें तो भी पांच हजार करोड़ के करीब का जो डिफिसिट है, आज तक भी अपने मुल्क में इतने बड़ डिफिसिट वाला बजट पेश नहीं हुआ है। यह बात उनको साफ तरीके से स्वीकार करनी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि इस तरह की स्थिति है और हमें यह करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है।

एक बात और है— 9 तारीख को बजट सेशन शुरू होने वाला था। उसके ठीक दो दिन पहले यह सब एनाउंसमेंट उन्होंने कर दिया। क्यों ? बजट आप पेश करने वाले थे। बजट में आप ने इसको क्यों नहीं रखा ? इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि इस हाउस का और इस सदन का यह एक प्रकार से अपमान है, कंटेम्प्ट है। जनता को मिसलीड करने की कोशिश तो है ही, इस सदन का भी अपमान है।

मैं वेंकटरामन साहब के बारे में बहुत अच्छी राय रखता हूँ और जल्दी से मैं अपनी उस राय को छोड़ने वाला नहीं हूँ और न ही इसके लिए तैयार हूँ। मैं मान लेता हूँ कि उनकी शायद यह गलती नहीं थी। उनके जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, उन्होंने ऐसा कर दिया है। लेकिन हार्ड फैक्ट यह है, ठोस तथ्य यह है कि मुद्रा स्फीति जो बड़ी से बड़ी होने वाली है आप उसको जानते थे और आप यह भी जानते थे कि आप एक पाप इस हाउस के साथ कर रहे हैं और दूसरे आपके मन में यह था कि आप मुद्रा स्फीति को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, इस इकोनॉमी का कोई क्योर आपके हाथ में नहीं है तो आपको इसको साफ स्वीकार करना चाहिए था। लेकिन नहीं। दिल में जो बात थी, इसको आप इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स कहिये या कुछ भी कहिये, दबाने की कोशिश आप कर रहे थे पानी पी.पी कर। एक घंटा 40 मिनट में दो-दो गिलास पानी पिया जा रहा था। चार-चार घंटे लोग बोले हैं लेकिन एक बूंद पानी नहीं पिया। इससे जाहिर होता है कि साइकोलॉजिकली आप कोई एस्केप ढूंढ रहे थे और वह आपको पानी पी कर मिला।

दूसरे यह, कि बिला वजह, जैसा कि मैं अभी साबित करूँगा, और तथ्यों के विरुद्ध उन्होंने मुझे मिस-रिप्रेजेंट और बदनाम करने की कोशिश की है, जो कि मैं उनसे उम्मीद नहीं करता था। मकवाना साहब बैठे हों, तो वह माफ करें, अगर वह होते तो बात समझ में आ सकती थी, अब आप तो सीनियर मिनिस्टर हैं और बाल भी आपके करीब-करीब मेरे बराबर सफेद हैं।

आपने यह कहा है कि पिछले साल खेत की पैदावार में 10 फीसदी की कमी हुई और राष्ट्रीय आय 3 फीसदी कम हुई। बेशक हुई, लेकिन क्यों हुई ? आपने स्वयं तीन जगह अलग-अलग पैराग्राफ्स में इस बात को तस्लीम किया है। उसके तीन कारण यह थे। एक तो यह कि एक्सेप्शनल ड्राउट, मामूली ड्राउट नहीं, कि महीने-डेढ़ महीने बारिश नहीं हुई। 1899 में सबसे बड़ी अनावृष्टि हुई तथा यह 1979 में हुई। तो एक तो यह वजह आपने खुद तस्लीम की है। आप कहते हैं पैरा 3 में अपनी स्पीच में —

That it was severe drought that was partly responsible, and in paragraph 8 that increases in prices of crude oil and oil products also contributed to inflationary pressures.

मैं आपको इस बात की स्वीकारोक्ति के लिए धन्यवाद देता हूँ।

Further, in paragraph 19, he admitted that the problem was compounded by almost total cessation of supplies from January onwards from the four refineries dependent on the Assam crude.

4 महीने, जनवरी से लेकर मई तक तेल आसाम से नहीं आया, उसके लिए तो आप सीधे जिम्मेदार हैं। तीन बातें आपने कही हैं कि इसकी वजह यह है। अगर यह बात आपको तस्लीम है, और आपको तस्लीम है, तो फिर आगे चलकर आप यह कहते हैं कि इस गवर्नमेंट को बिरासत में डिस्मल इकोनॉमिक सिचुएशन मिली है, आर्थिक स्थिति ऐसी मिली है, जो बहुत दुःखदायक है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? यह इस गवर्नमेंट को प्रीवियस गवर्नमेंट से विरासत में मिली, यह तीन कारण आपने स्वयं तस्लीम किये हैं, इनके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मनी सप्लाय में इतनी इन्फ्लेज हुई है, रुपया लोगों की जेब में इतना गया है कि क्रय शक्ति आज तक इतनी कभी नहीं हुई।

सन् 1976-77 में जो कांग्रेस रूल था, तब मनी सप्लाय आपकी बढ़ी है 20.3 परसेन्ट। उससे पहले कभी इतनी नहीं बढ़ी थी। यह आपका आखिरी साल था। अगले साल जनता गवर्नमेंट के जमाने में 14.7 परसेन्ट और 77-78 में 19.8 परसेन्ट। तो तीन साल तक इतनी बढ़ी, अगर आप इसको घटायें तो 75-76 की फिगर्स पर तो 80 परसेन्ट, अगर 100 रुपये मनी सप्लाय थी पब्लिक के पास तो 79 में वह 180 रुपये हो गई। यानी लोगों की क्रय-शक्ति दुगुनी हो गई, परचेजिंग पावर बढ़ गई। तो यह फैक्ट आपकी नजर से ओझल नहीं होना चाहिए था, आपको इसे तस्लीम करना चाहिए था। अब बेशक जनता गवर्नमेंट के सामने बढ़ी थी, आप सबसे ज्यादा कर चुके थे।

इसके अलावा यह भी बात ध्यान में रखने की है कि जो ड्राउट हुआ तो उसमें पैदावार वैसे ही कम हुई, लेकिन हमारे यहां के ट्रेडर्स नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करते हैं यह भी मिज़री है। अनावृष्टि हो जाये, अतिवृष्टि हो जाये, लोकस्ट की मार हो जाये तो हमारे यहां टेंडेंसी यह है कि मनी-लेंडर्स, ट्रेडर्स, होलसेलर्स हर आदमी मासेस को एक्सप्लॉयट करता है और उसका ज्यादा फायदा उठाना चाहता है।

परमात्मा न करे, अगर हमारे यहां लड़ाई शुरू हो जाये और किसी शहर में बॉम्बिंग हो जाये तो हमारे यहां 24 घंटे में आप देखेंगे कि ट्रेडर्स 50 फीसदी प्राइसेज बढ़ा देंगे। सेकिंड वर्ल्ड वार में 1939

से लेकर '45 तक लन्दन में बराबर बॉम्बिंग होती रही लेकिन केवल 10 परसेंट ही प्राइसेज वहां बढ़े, जबकि यहां यह देखकर कि सूखा पड़ा है, ट्रेडर्स और होलसेलर्स ने गुड्स होते हुए भी दाम बढ़ाने की कोशिश की। इसका कोई लिहाज नहीं कि गुड्स की अवेलेबिलिटी है या नहीं। उन्होंने सोचा कि चूंकि सूखा पड़ा है, किसान और जनता परेशान है, शहरों के कनज्यूमर परेशान हैं, इसलिए दाम बढ़ाओ।

प्राइसिज को रेस्ट करने, रोकने के लिए हम एक ऑर्डिनेंस लाये। माननीय इंदिरा जी नहीं हैं, लेकिन मुझे उनकी स्पीच याद है, जो उन्होंने पार्लियामेंट के इलेक्शन्स से पहले दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह आर्डिनेंस मुझे गिरफ्तार करने के लिए लाया गया है। कहां जा कर बात लगी? एसेंशियल कमोडिटीज की सप्लाई को बनाये रखने के लिए यह आर्डिनेंस लाया गया था— हमारा तो केवल आर्डिनेंस था, आपने उसको एक्ट बनाया— लेकिन उसके बारे में आपकी लीडर कहती थीं कि दरअसल ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। बजाये लोकदल की गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के आपने उसका पॉलीटिकल एडवान्टेज उठाने की कोशिश की। अगर कोई शुगर को स्टोर करेगा या प्राफिटियरिंग करेगा, तो उसे गिरफ्तार किया जायेगा, लेकिन महज प्रपोगेंडा के लिए ऐसी बातें कही गईं। अफसोस की बात यह है कि आपने स्वयं उस ऑर्डिनेंस को एक्ट बनाया। जब आप नवम्बर-दिसम्बर में उसको कंडेम कर रहे थे, तो आपने एक्ट क्यों बनाया ? इन फैक्टर्स की वजह से भी प्राइसिस बढ़ीं।

1965-66 में मामूली सा सूखा पड़ा— यह नहीं कि तीन-चार महीने बराबर सूखा पड़ा— लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर पाई। नतीजा यह हुआ कि 1965-66 में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन 16.6 परसेंट और 1966-67 में 16.7 परसेंट घट गया। 1979 में वह केवल 10 परसेंट घटा। ये इकोनॉमिक रिव्यू की फिगर्स हैं। मैं फिर कहता हूँ कि ड्राउट नहीं था, सिवियर ड्राउट तो दरकिनार, मामूली ड्राई स्पेल से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन दो साल तक 16.6 परसेंट घटता रहा।

आपने एनालेसिस में इन्फ्रास्ट्रक्चर के ठीक वर्क न करने की बात कही है। मैं उसको तस्लीम करता हूँ, लेकिन उसके लिए जिम्मेवार कौन है ? आपके जरिये मैं अपने माननीय मित्र से कहना चाहता हूँ कि अगर कोई जिम्मेवार है, तो आप, आपके प्रीडेसेसर और आपकी पॉलीटिकल पार्टी। इन्फ्रास्ट्रक्चर में बातें तो बहुत सी हैं कहने को, लेकिन आज समय नहीं है, मौका भी नहीं है। मैं तीन बातों का जिक्र करना चाहता हूँ : कोल, पावर और ट्रांसपोर्ट। इनमें विलेन आफ दि पीस है कोल। कोल को किसने नेशनलाइज किया ? नेशनलाइज के बाद कोल की कीमत बढ़ती चली गई, स्ट्राइक्स होती रहीं और 45,000 बोगस वर्कर्स के नाम कागजात में दर्ज हैं, जिसकी वजह से 32 करोड़ रुपये सालाना गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ता है। मैं इसके लिए जनता गवर्नमेंट को भी दोषी मानता हूँ... लोक दल गवर्नमेंट को मौका नहीं मिला— और उस गलती के लिए मैं अपने आप को जिम्मेदार मानता हूँ। लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट दस साल तक बराबर पोजीशन खराब कर चुकी थी। जब कभी कोल वर्कर्स ने ब्लैकमेल करना चाहा, तो गवर्नमेंट ने हमेशा उनके सामने घुटने टेक दिये। इसका इफैक्ट पावर और ट्रांसपोर्ट पर होना ही था।

कोल ही नहीं, और भी बहुत सी चीजें हैं। अगर इन समस्याओं को हल करना है, तो हार्ड डिसिजनस लेने पड़ेंगे और अगर जरूरी हो, तो सब पॉलीटिकल पार्टिज को मिलकर लेने होंगे। कौन नहीं चाहता कि वर्कर्स और गरीब लोगों को सहूलियत मिले? लेकिन सिर्फ आर्गनाइज्ड वर्कर्स ही गरीब नहीं हैं, जो ब्लैकमेल कर सकते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, जिनका कोई जिक्र न असेम्बली में होता है न इस सदन में होता है, उनसे दस गुना, पन्द्रह गुना ज्यादा हैं, जिनकी कोई फिक्र नहीं है। जो स्ट्राइक कर सकते हैं उनके लिए तो सारी पॉलिटिकल पार्टिज मदद करने को तैयार हैं। अब इन्फ्रास्ट्रक्चर खराब है तो उसके लिए प्रीवियस गवर्नमेंट, जनता या लोक दल गवर्नमेंट तो जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए अगर कोई गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार है, तो वह जनाब की पॉलिटिकल पार्टी है।

आप आगे कहते हैं कि सूखे से रिलीफ के लिए बहुत बड़ा इंतजाम कर रहे हैं। कौन सा नया इंतजाम कर रहे हैं जो लोकदल गवर्नमेंट ने नहीं किया? उल्टे आप ने बिगाड़ा है। मैं बतलाता हूँ कि कैसे बिगाड़ा। हमने रिग्स का इंतजाम किया। रिग्स की जरूरत मध्य प्रदेश में, जहाँ पर कि बहुत पथरीली जमीन है, जहाँ आसानी से पानी निकाला जा सकता, सबसे ज्यादा है। इसके लिए एक जो उनका सर्वे है, उनसे हमने पूछा कि क्या उनके यहाँ रिग्स अवेलेबल हैं; और कोई एजेंसीज या इंस्टीट्यूशन इसके लिए हैं, उनसे पूछा। नहीं थे। लिहाजा सारे एम्बेसेडर्स को कांटेक्ट किया कि फारेन गवर्नमेंट्स जितनी रिग्स दे सकती हैं, उनको वह फौरन खरीद लें। दूसरे देशों के जितने एम्बेसेडर्स अपने मुल्क में हैं, अपनी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से उनको कॉन्टैक्ट किया और सैकड़ों रिग्स मंगाने का इंतजाम किया। उसको एयरलिफ्ट करने का इंतजाम किया। मैं सबजेक्ट टु करक्शन बोल रहा हूँ, मैंने सुना है कि जब जनाब की गवर्नमेंट ने चार्ज लिया तो उसमें ढील आई। बाद में शायद रिग्स मंगाये या नहीं, मुझे नहीं मालूम।

आपने कहा कि आपने कमेटी बना दी, यह कर दिया, फूड फार वर्क प्रोग्राम लागू कर दिया। यह कोई नई चीज आपने नहीं की है। तो क्यों आप उसके लिए क्रेडिट लेते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आया।

एक बात आगे कहते हैं कि कोई बिल ला रहे हैं होटल की ग्राँस रिसीट्स पर टैक्स लगाने के लिए और आप उसका क्रेडिट ले रहे हैं, मानो यह आपकी ब्रेन-वेब है। यह भी गलत है। इस बिल के लिए तो मैं खुद ही कह गया था और मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। आपको यह कहना चाहिए था कि चरण सिंह पिछली बार जो कह गये हैं, उसके अनुसार गवर्नमेंट बिल ला रही है। यह आपने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? आपको कहना चाहिए था। गाली तो आपको सब याद रहती है। खैर, वह इसमें दे रखा है, इस समय मिल नहीं रहा है। इसमें मौजूद है पहले से कि जो अलग-अलग आइटम्स हैं उन पर सेल्स टैक्स स्टेट गवर्नमेंट्स को लगाने का अधिकार है, लेकिन ग्राँस रिसीट्स पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगाना चाहती है, तो उसमें क्या कठिनाई है? अगर कोई है तो उसके लिए यह भी मेरी स्पीच के अन्दर दिया हुआ है कि हम एक अफसर एप्वाइंट कर रहे हैं और एक बिल लायेंगे। आपको कहना था कि प्रीवियस जनता गवर्नमेंट, जो यह वादा कर गई थी, उस पर हम अमल कर रहे हैं। लेकिन आपने नहीं कहा।

फिर आपका कहना है, जनरल बात है कि कॉमन मैन के लिए आप कर रहे हैं। कॉमन मैन की जनाब की क्या डेफिनीशन है? कॉमन मैन यहाँ नहीं रहता है। दिल्ली में जो रहते हैं, उसमें 26 परसेंट कॉमन मैन है, सबसे कम। जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, जो पेवमेंट्स पर रह रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ उसके लिए इस बिल में कोई प्राँविजन है? जो टैक्स देने वाले हैं उनके लिए रिलीफ है। लेकिन टैक्स देने वाले कितने लोग हैं? वह कॉमन मैन तो नहीं है। कॉमन मैन की जनाब की डेफिनीशन क्या है? आपकी कॉमन मैन की डेफिनीशन है — इंडस्ट्रियलिस्ट्स, उनके मैनेजर्स, उनके इंजीनियर्स, उनके टैक्नीशियंस, उनके कैमिस्ट्स, होलसेलर्स, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट करने वाले, बड़े-बड़े ट्रेडर्स और कमीशन एजेंट्स, ट्रांसपोर्टर्स वगैरह-वगैरह और पालिटिशियंस, जर्नलिस्ट्स, डाक्टर्स, बड़े-बड़े लॉयर्स, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स— यहाँ आपके कॉमन मैन की लिस्ट एग्जास्ट हो जाती है लेकिन ये कॉमन मैन नहीं हैं।

आपके सारे प्रपोजल्स क्या कॉमन मैन के लिए हैं— यह मैं जानना चाहता हूँ। कॉमन मैन कौन है? आज 55 फीसदी लोग बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, बिलो द सॅब्सटेंन्स लेवल रह रहे हैं। 1976-77 के रेट्स के हिसाब से साढ़े 47 फीसदी लोग थे और आज प्राइसेज बढ़ गई हैं इसलिए शायद 60 फीसदी भी हों। मैं जानना चाहता हूँ इन लोगों के लिए आपने इसमें क्या रखा है? क्या हम लोग कॉमन मैन हैं? यहाँ दिल्ली में जो सड़कों पर दिखाई देते हैं, महलों में रहते हैं, मोटरों पर आते-जाते हैं— क्या वे

कॉमन मैन हैं? फिर गरीब आदमी के लिए, विलेजर के लिए आपने क्या किया और उन गरीबों के लिए आपने क्या किया है जिनके घर में कोई सामान नहीं है?

आपने जो रिलीफ दी है, उसको एक मिनट के लिए देखें कि कॉमन मैन उससे कहां तक अफेक्टेड है? आपने इनकम टैक्स में एग्जेंप्शन लिमिट 10 हजार से बढ़ाकर 12 हजार कर दी है, बहुत अच्छा है। एक हजार रुपये फी महीने हो गया। इससे जो लोग रिलीफ पायेंगे उनको बहुत अच्छा लगेगा। मेरे ख्याल में 20 हजार कर देते तो और अच्छा लगता लेकिन इसमें आप कॉमन मैन की बात मत कहिए। आप सीधी-सीधी बात कहिए कि जो हमारे मिलने-जुलने वाले हैं, हमारी सोसायटी में रहने वाले लोग, जिन्होंने मॉडर्न स्टाइल ऑफ लिविंग अख्तियार कर ली है, वही हमारे कॉमन मैन हैं। वही क्लब में मिलते हैं, वही टहलते हुए मिलते हैं, वही एरोप्लेन में मिलते हैं, वही हमारे दोस्त हैं और वही कॉमन मैन हैं।

इसी तरह से इनकम टैक्स में ऊपर की मैक्सिमम लिमिट को भी आपने 72 से घटाकर 66 परसेंट कर दिया, वह भी उनको अच्छा लगा होगा। अगर किसी इंडस्ट्रिअलिस्ट से आप पूछते तो शायद यही कहता कि 50 परसेंट और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे उनको रिलीफ पहुंचती है। यही नहीं, बीच के जो स्लैबज हैं उनके रेट्स भी आपने गिराये हैं। इसके अलावा वैल्यू टैक्स की एग्जेंप्शन लिमिट भी आपने एक लाख से डेढ़ लाख बढ़ा दी। क्यों ? इसको एक लाख क्यों नहीं रहने दिया? अगर प्राइसेज बढ़ रही हैं तो उससे सारा देश अफेक्टेड होगा। फिर वैल्यू किसको कहते हैं? यह कम्पैरेटिव टर्म है। बहुत से लोगों के लिए तो डेढ़ लाख भी कोई वैल्यू नहीं है, उनके लिए तो 10 लाख चाहिए लेकिन आम आदमी के लिए एक लाख बहुत बड़ी चीज है।

फिर आपने किसानों के लिए एक बहुत बड़ी मेहरबानी कर दी है कि उनको वैल्यू टैक्स से एग्जेंप्शन कर दिया लेकिन इससे कितने किसान अफेक्टेड हैं? आपने करप्शन की बात मानी है और कहा कि उसका असेसमेंट करना है कि कितना टैक्स है, कितनी वैल्यू है— यह ठीक है लेकिन यहां पर यह इम्पेक्षन पैदा करना और जिस पर अपने दोस्तों से यहां पर ताली पिटवाई कि किसानों को वैल्यू टैक्स से मुक्त कर दिया, मानो करोड़ों किसान इससे अफेक्टेड हों। अगर मुझे ठीक से याद है तो शायद 16 हजार आदमी थे, जो वैल्यू टैक्स गांवों में देते थे जिनमें नान-एग्रीकल्चरिस्ट भी थे, जबकि यहां केवल दिल्ली में 19 हजार ऐस लोग हैं जो वैल्यू टैक्स देते हैं। तो इससे कितने किसान अफेक्टेड हुए? तो यह आपकी वैल्यू टैक्स की बात रही। अगर इस क्षेत्र में मैंने कुछ कर दिया होता, तो मैं कुलक हो जाता, मैं यहां पर लैण्ड रिफॉर्म की बात नहीं करना चाहता, वरना बतलाता कि कुलक कौन है। अभी मैं एक किताब लिख रहा हूँ, जिसका एक चैप्टर इसी सबजेक्ट पर है “हू आर द कुलक्स”\* वह मैं आपके पास भेज दूंगा, जिसमें आप पायेंगे कि वे सभी उस तरफ बैठे हैं।

आप कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट पर, पब्लिसिटी पर, सेल्स प्रमोशन पर जितने टैक्स हैं, वह सब आपने हटा लिया, क्योंकि इंडस्ट्रिअलिस्ट, मनीलैण्डर और रिचमैन जो हैं, आपका ध्यान रह-रहकर उन्हीं पर जाता है कि उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात आप करते हैं, जिसके लिए 3 सौ करोड़ /रुपया, पता नहीं और कितना हो लेकिन 3 सौ करोड़ से कम नहीं है, जबकि हमारी इन्टरनल प्राइसेज से एक्सटर्नल प्राइसेज हायर हैं, वहां पर इन्फ्लेशन-रेट बहुत जबर्दस्त है, फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए सब्सिडाइज करने की क्या जरूरत है? कम्पीट करने की एबिलिटी तो उनमें वैसे ही होनी चाहिए। आज इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेज बहुत हैं, फिर भी तीन सौ करोड़ रुपया गरीब आदमियों से लेकर मालदार आदमियों को देकर आप उनको और मालदार बना रहे हैं। यह सब्सिडी उनको मिलती है जो कि उसके लिए इन्टाइटिल्ड नहीं हैं। इसमें इतनी खराबी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके करप्शन की डिटेल्स में जाइये।

इसके अलावा मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, इंडस्ट्रिअल नीड्स में, ठीक है कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें आप कम्पीट कर सकते हैं लेकिन जनरल इंडिया और पॉलिटिकल लीडर यह समझते हैं

कि दूसरे देशों को मशीन वगैरहा भेज कर कम्पीट कर सकते हैं, मैं कहता हूँ कि कभी नहीं कर सकते हैं। एक ही चीज में कम्पीट कर सकते हैं और जिसकी जरूरत है, वह है— फूड प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट। आप फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने की तरफ ध्यान दीजिए और अभी वर्ल्ड फूड काउंसिल की हालत क्या है, दो और इंस्टीट्यूशंस की हालत क्या हैं? बहुत से कन्ट्रीज हैं, जहां फूड शॉर्टेज होने वाला है। इस चीज को देखते हुए हमको यह फायदा उठाना चाहिए कि फूड की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए। उसमें आप कम्पीट कर सकते हैं, इसमें आप इतना फॉरेन एक्सचेंज कमा सकते हैं कि हमारी फॉरेन एक्सचेंज की जितनी भी रिक्वायरमेंट है, वह आसानी से पूरा हो सकती है और उसका इफेक्ट जो हमारी इकोनॉमी पर पड़ेगा, वह इनकैलकुलेबल है। आज हम 125 करोड़ टन पैदा कर रहे हैं। क्यों नहीं 250 टन कर सकते हैं? कुछ ऐसी कन्ट्रीज भी हैं जो 5-7, 7-8 गुना फी एकड़ पैदा करती हैं, हम भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? लेकिन इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। किसान तो गंवार आदमी है, वह दो एकड़ का भी कुलक है, वे तो गाली देंगे ही। अगर देश की इकोनॉमी को रिडीम करने वाले पांच-छह स्टैप्स हैं, तो एक स्टैप यह है कि mere attention to food production; we should be able to produce so much that we are able to export millions and millions of tonnes of foodgrains.

तब देखिये कितना फायदा होता है। ये चन्द लोग हैं, आप जरा ऐसा कीजिए कि अपने सी0बी0आई0 या आई0बी0 से पूछिए कि फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन से कितने लोगों को बम्बई में फायदा हो रहा है, कितने लोग बेईमानी से अफसरों से मिलकर और सब्सिडी के नाम पर रुपया कमाते हैं।

आप कहते हैं कि कस्टम ड्यूटी हमने हटाई है, मशीनरी और इन्स्ट्रुमेंट्स पर। किसके लिए, इलैक्ट्रॉनिक्स के लिए। इलैक्ट्रॉनिक कौन सी बड़ी भारी चीज है। इलैक्ट्रॉनिक्स ठीक है, हमारे एयरोप्लेन वगैरहा के लिए कुछ स्पेशल डिपार्टमेंट्स हैं, उनके लिए है लेकिन जो आपने पैरा 103 और 104 में इम्पार्ट्स दी है कि इलैक्ट्रॉनिक्स कम्प्यूटर इन्डस्ट्रीज बढ़ने से एम्प्लायमेंट बढ़ेगा, मैं जानना चाहता हूँ कि इलैक्ट्रॉनिक्स की जो इन्डस्ट्री है, उनसे एम्प्लायमेंट बढ़ेगा, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपने जानने की कोशिश की है कि कितने लोग एम्प्लायड हैं और कैसे इससे एम्प्लायमेंट बढ़ेगा।

आज अन-एम्प्लायमेंट की क्या हालत है और क्यों हर साल बढ़ता जा रहा है, क्या उसके लिए किसी ने सोचा है? नहीं। क्योंकि अनएम्प्लायड आदमी अपनी मुसीबत को बताने के लिए यहां नहीं है। जो अखबार निकलता है, वह भी जो फुली एम्प्लायड हैं, उनके लिए निकलता है। आप कहते हैं कि इलैक्ट्रॉनिक्स की जो इन्डस्ट्रीज हैं, उनसे एम्प्लायमेंट बढ़ेगा, मुझे बहुत ताज्जुब हुआ और आप पर मुझे दया आती है।

आप कहते हैं कि एक्साइज ड्यूटी चीपर टेलीविजन सेट्स पर कम की है, क्यों? क्या ये टेलीविजन सेट्स कॉमन मैन को चाहिए? मैं गिनाऊंगा उन चीजों को भी जो चरण सिंह ने की हैं और आपने माफ कर दिया है। अब 55 पर्सेंट आदमियों को फूड नहीं मिल रहा है, तो आप फूड प्रोडक्शन पर रुपया लायेंगे या आपको फिक्र पड़ी है घर-घर में टेलीविजन सेट्स पहुंचाने की। क्या हम लोगों का यह नजरिया हो गया है कि हर घर में टेलीविजन सेट होना चाहिए? टेलीविजन सेट वाले लोग आपसे मिलते-जुलते हैं, इसलिए आपको उनकी फिक्र पड़ी है— क्या ये कॉमन मैन हैं?

आप कहते हैं— इलैक्ट्रॉनिक्स कम्प्यूटर्स पर एक्साइज ड्यूटी कम करने से एम्प्लायमेंट बढ़ेगा। वैकटरामन जी, आप बुरा न मानें। अभी 1978-79 में आस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर यहां आये थे, हमारी गवर्नमेंट से मिलने के लिए। उसमें कुछ नोट्स तैयार हुए, कुछ उनकी इकोनॉमी की बावत, कुछ हमारी इकोनॉमी की बावत तथा कुछ बातें इकोनॉमिक मैटर्स पर भी हुईं। आपको ताज्जुब होगा यह जानकर कि कम्प्यूटर, इलैक्ट्रो प्रोसेसिंग वगैरह से यह नतीजा हुआ कि आस्ट्रेलिया जैसे देश में, जिसके पास ढाई गुना जमीन है, जिनकी कुल आबादी इतनी है जितनी कि यहां एक साल में बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी वे लोग आज अन-एम्प्लायमेंट से सफर कर रहे हैं।

इस मुल्क में हर साल डेढ़ करोड़ आबादी बढ़ जाती है और 50 लाख लड़के 16 साल की उम्र के हो जाते हैं, वर्किंग फोर्स में शामिल हो जाते हैं और आप कहते हैं कि इलैक्ट्रिक कम्प्यूटर्स से उनको एम्प्लायमेंट मिलेगी। लेकिन जिस मुल्क की कुल आबादी डेढ़ करोड़ है और जहां पर इतने नेचुरल रिसोर्सेज और मैटीरियल रिसोर्सेज अवेलेबिल हैं— वह मुल्क अन-एम्प्लायमेंट से सफर कर रहा है। हमारे नोट्स में यह बात थी, आप चाहेंगे तो मैं भेज दूंगा।

मेरी समझ में नहीं आ रहा है— हम लोग जमीन से अलग होकर हवाई बातों में, अखबारों को पढ़कर, अमेरिका या इंग्लैण्ड जाकर क्या सीख कर आते हैं? गलत आइडियाज लेकर आते हैं, बजाए इसके कि हम अपनी ही बातों पर अमल करें। मेरी समझ में नहीं आ रहा है— इलैक्ट्रिक कम्प्यूटर्स पर क्यों इतना जोर दिया गया है? क्या इस तरह से गरीबों के मसलों को हल करेंगे?

सभापति महोदय, हाई प्रेशर गैस सिलेण्डर्स के लिए स्टील ट्यूब्स इम्पोर्ट करने पर टैक्स की छूट दी गई है। ठीक है, ये गैस सिलेण्डर्स हमारे यहां इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कितने घरों में? गांव में चूल्हा कैसा बनना चाहिए, उसके लिए कैसा पयूल चाहिए, उस पयूल की कितनी कमी गांवों में हो गई है— इस पर कोई ध्यान नहीं है बल्कि हाई प्रेशर सिलेण्डर्स स्टील ट्यूब्स के इम्पोर्ट पर टैक्स को घटा दिया।

टैक्स-हॉलिडे को लीजिए। टैक्स हॉलिडे हम ने भी किया था, लेकिन प्रायोरिटी सेक्टर के लिए किया था। लेकिन आपने 11वें शेड्यूल में जो चीजें गिनाई हैं, उनमें नान-प्रायोरिटी सेक्टर की चीजें भी शामिल कर ली हैं। आप दोनों को क्यों दे रहे हैं? जो चीजें प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं आती हैं, जो हमारे लिए गैर-जरूरी हैं उनको टैक्स हॉलिडे में शामिल करने के क्या मायने हैं? हमने भी पिछले बजट में दिया था, लेकिन प्रायोरिटी सेक्टर को दिया था, आपने दोनों को क्यों दिया? मालूम होता है— कुछ दोस्तों को इलैक्शन के वक्त सब इंडस्ट्रीयलिस्ट्स आकर मिल गये हैं।

डेप्रिशियेशन पहले जितना था, उससे 50 पर्सेन्ट और ज्यादा कर रहे हैं। डेप्रिशियेशन की बात समझ में आ रही है, इम्पोर्ट ड्यूटी की बात समझ में आ रही है— लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि यह सब किसके लिए हो रहा है? यह सोसायटी के सिर्फ 10-15 पर्सेन्ट लोगों के लिए हो रहा है, गरीब के लिए कुछ नहीं हो रहा है। आपके इस एटीट्यूड का नतीजा क्या हो रहा है? इसका नतीजा यह हो रहा है कि आज इनवेस्टमेंट हो रही है— सब लक्जरी आइटम्स में हो रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जनवरी, 1980 में एक स्टडी पब्लिश हुई है, जिसमें उन्होंने साढ़ आठ साल के इन्वेस्टमेंट का हिसाब लगाया है, जून 1979 तक का हिसाब लगाया है, मैं उसका एक पैरा आपको पढ़ कर सुनता हूँ —

"The Study relates to a period of 8.5 yaers upto the first half of 1979. While the annual combined rate of growth for consumer goods was less than 3.9 percent....."

वनस्पति, शुगर, जूते या जो भी कंज्यूमर गुड्स हैं, उनका कम्बाइण्ड रेट ऑफ ग्रोथ 3.9 परसेंट था। लेकिन दूसरी चीजों की क्या हालत है— शराब का 287 परसेन्ट था। शराब कौन पीता है? शराब बड़े आदमी पीते हैं और टैक्सों को कम करके आपने शराब पिलाने का इंतजाम कर दिया, उसमें कोई कमी नहीं हो रही है। परफ्यूमज का 435.3 परसेन्ट हो गया, एयर कण्डीशनर्स और रेफ्रीजरेटर्स का 249.7 परसेन्ट हो गया, वॉचेज एण्ड क्लॉक्स का 290.5, कॅमर्शियल हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स का 215.7 परसेन्ट, इलैक्ट्रिक फैनस का 232.1 परसेन्ट, इलैक्ट्रिक लैम्प्स 189.7 परसेन्ट। शायद आपको इससे तसल्ली होगी कि ऐसा करने से देश का एक बड़ा भारी डेवलपमेंट होगा लेकिन वास्त मासेज के लिए केवल 3.79 परसेंट है जबकि वह 85 परसेंट है। अगर आप एकोनॉमी को पुराने रास्ते पर ही ले जाना चाहते हैं, तो कन्ट्री इज डीमड। इसलिए कुछ हार्ड थिंकिंग आपको करनी चाहिए। उसी तरह से चलते रहे जैसे 25-30 साल तक आप चले हैं, तो उससे काम चलने वाला नहीं है। उसको चेंज करना चाहिए।

सन् 1917 में महात्मा गांधी जी चम्पारण गये थे, जबकि ब्रिटिश इन्डीगो प्लान्टर्स, इंडियन पीजेन्ट्स को तंग कर रहे थे। जब वे सड़क से गुजर रहे थे— सड़कें जो गांवों से होकर, गांवों के बराबर होकर या गांवों के बीच से होकर जाती हैं— तो गांवों के लोगों ने सुन रखा था कि कोई बड़ा आदमी आ रहा है, हमारी मुसीबतों को स्टडी करने के लिए। उस समय महात्मा जी ने यह देखा कि जितने लोग आये थे, खास तौर पर उनका ध्यान औरतों की तरफ गया और उन्होंने देखा कि वे सब मैले कपड़े, निहायत मैले कपड़े पहने हुए थीं। तो थोड़ी दूर चल कर उन्होंने माता कस्तूरबा को भेजा उनसे पूछने के लिए कि माना गरीबी है, फिर भी वे कपड़े क्यों नहीं धो सकतीं। जो धोती पहन रही थीं, उनको वे धो सकती थीं। मालूम है क्या जवाब दिया उन्होंने? उन्होंने जवाब दिया कि हमारे पास केवल एक ही धोती है, कैसे चेंज करें, कैसे नहाये, कैसे धोयें। मैं वेंकटरामन साहब से गुजारिश करूंगा हाथ जोड़कर और मैं यह चाहूंगा कि आप दिल्ली की हवा छोड़कर बिहार के एक-दो दोस्तों के साथ चम्पारण के गांवों में आज भी चले जाएं, तो आप पायेंगे Exactly the same condition exists today.

उनके पास आज भी कपड़ा नहीं है। उनके घर जाइये और देखिये कि क्या चीज है? उस तरफ कभी आपका ध्यान नहीं गया है। बहुत से ऐसे घर हैं, जहां पर दो महिलाएं हैं और तीन धोतियां हैं। बारी-बारी से आकर वे नहाती हैं और ऐसे करोड़ों घर हैं, जहां पर एक ही थाली है। एक आदमी खाना खा लेता है, फिर वह मंजती है तब दूसरे का नम्बर आता है। फाइनेन्स मिनिस्टर साहब कहते हैं कि आपने Sweeping taxation on articles of common consumption लगा दिया! आपने यह मुझ पर चार्ज लगाया, लेकिन आपने क्या-क्या एग्जम्पशन्स दिये हैं, वे सुनिये। आप कहते हैं कि — cycles and sewing machines इसमें आपका कहना यह है कि मैंने इन पर टैक्स लगाया था। आपका यह कहना है लेकिन मैंने टैक्स लगाया ही नहीं। पहली बात तो यह है। आप मेरी स्पीच का पैरा 119 देखिये।

मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने टैक्स लगाया नहीं साइकिल्स पर बल्कि जो मोपेड होती है, जो एक तरह की साइकिल होती है, उस पर टैक्स कम किया था। साइकिल्स पर टैक्स लगाया नहीं nothing of the kind. सुइंग मशीन्स पर भी नहीं लगाया।

फिर आपने जिक्क किया है लाइफ सेविंग ड्रग्स का। आप कहते हैं कि इन पर हम टैक्स माफ कर रहे हैं। मैंने लाइफ सेविंग ड्रग्स पर टैक्स नहीं लगाया था। आप मेरी स्पीच का पैरा 108, 109 देखिये। मेरे पास वह है, मैं पढ़ कर सुना सकता हूँ। हमने उन पर टैक्स माफ किया था, आपने ज्यादा माफ किया, यह आप कह सकते हैं लेकिन मैंने उन पर टैक्स नहीं लगाया था। मैं पैरा 109 पढ़कर सुनाता हूँ —

"I would also refer to the relief in the field of drugs and medicines. I propose to fully exempt from customs duties 27 specified bulk drugs required for the formulation of life-saving drugs and to reduce the customs duty on 17 specified bulk drug intermediates from a total of 75% ad valorem to 25% ad valorem."

मैंने तो घटाया है। आपके लफ्जों से ऐसा लगता है कि मैंने बढ़ाया है। यह बहुत अन्याय है मेरे साथ। फिर आप कहते हैं कि प्रेशर कुकर पर मैंने टैक्स लगाया है। प्रेशर कुकर एक ड्यूरेबल आइटम है, यह बीस सालों तक चलती है, इसलिए उस पर लगाया था। इसमें आपने छोड़ दिया है तो कोई गरीब आदमी को बड़ा भारी रिलीफ दे दिया है? अगर नहीं तो इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं थी। आप बेशक कम कर दें लेकिन यह मेंशन करके आप इम्प्रेसन क्या देना चाहते हैं?

अब चीपर वैरायटी ऑफ टूथ पेस्ट और टूथ ब्रश को बात है। उनके बारे में जो मैंने कहा था वह यह है —

"I have also selected some consumer items like soap, tooth-paste, tooth-brush and detergents for increase in duties, taking care, at the same time, to see that the goods produced by the small



units in the decentralised sector are not adversely affected by this increase. Excise duties will go up on household and laundry soap.....etc.etc."

आपके ये टूथ ब्रश और टूथ पेस्ट्स कौन बना रहे हैं? ये मल्टी नेशनल बना रहे हैं। जो बड़े हाउसिंग इन्हें बना रहे हैं, चाहे वे अपने यहां के हों या दूसरे देश के हों उनको पढ़े-लिखे लोग इस्तेमाल करते हैं। बहुत-सी चीजें जो पढ़े-लिखे लोग इस्तेमाल करते हैं वे सब मल्टी नेशनल कम्पनीज पैदा करती हैं। लेकिन मैंने केवल टूथ-ब्रश और टूथ-पेस्ट्स पर बढ़ाया है और वह भी उन पर नहीं बढ़ाया है, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज में बनती हैं, उन पर तो बल्कि घटाया है। It is just to get chairs from our friends here.

फिर आप वैक्यूम गैस फिल्ड बल्ब की बात करते हैं। इन पर भी हमने टैक्स माफ किया है। दो किस्म के बल्ब होते हैं। उनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि हमने बल्ब पर कम किया है।

"In restructuring the duty rates on consumer products I have reduced the incidence on a number of items by exempting them from special excise duty. I would like to make particular mention of the duty reduction from 42% to 30% on fluorescent lighting tubes which are widely used for street lighting and which help in reducing the consumption of electricity. I also propose to extend the scope of the present excise exemption for low price footwear valued upto Rs. 5 per pair to footwear valued upto Rs. 15 per pair."

तीस रुपये तक के जूते पर एग्जम्प्ट किया है। उससे अधिक के जूते पर जो पहले दस रुपये था, शायद उस पर बीस कर दिया था। लेकिन फ्ल्यूरोसेंट लैम्प, जिस पर बिजली कम खर्च होती थी, उस पर हमने 42 परसेंट के बजाए 30 परसेंट टैक्स किया था। मान लो कि इन पर हमने बहुत लगा दिया तो आपने उन पर माफ क्यों नहीं कर दिया? आप इन पर एक्साइज ड्यूटी माफ कर सकते थे। मेरे जमाने की बजट स्पीच में दिया हुआ है कि पहले साल की 5 हजार 2 सौ करोड़ रुपये की एक्साइज ड्यूटी मेरे जमाने में जो थी, वह आपकी हो गयी 6 हजार 205 करोड़। आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। बहुत सी चीजों पर आपने माफ की है। 691 करोड़ में से 35 करोड़ की आपने माफ कर दी है। जो पहले थी वह तो रह गई है। मैं फिर दोहराता हूँ कि स्टेट्स का शेयर शामिल करके मेरे जमाने में 641 करोड़ थी। उसमें से आपने 35 करोड़ कम कर दिया लेकिन 440 करोड़ उसमें और बढ़ा दिया। इस तरह से आप 606 करोड़ और 440 करोड़ मिला दीजिए। यह 1046 करोड़ हो जाता है।

These are the hard facts.

मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपने घटाया नहीं है, आपने बढ़ाया है। अगर आप करना चाहते थे तो क्यों नहीं आपने इन एक्साइज ड्यूटीज को एक कलम से खत्म कर दिया ? मैं आशा करता हूँ कि जब आप जवाब देंगे तो इसका जवाब देने की भी आप कोशिश करेंगे।

अब मैं गरीब आदमी पर आता हूँ। ये जो 50-55 परसेंट हैं इनका कहीं कोई जिक्र नहीं है। विलो पॉवर्टी लाईन वालों का कहीं कोई जिक्र नहीं है, नॉट ए वर्ड इज देअर। क्यों इनका जिक्र नहीं किया गया है ? पॉवर्टी को किस तरीके से आप खत्म करना चाहते हैं? कोई उनके बारे में तजवीज नहीं रखी गई है। पढ़े-लिखे लोग, अंग्रेजी जानने वाले लोग, मॉडर्न स्टाइल ऑफ लिविंग में जो विश्वास करते हैं, फॉरेन कंट्रीज की जो नकल करते हैं, जो शहरों में रहते हैं, वही हमारे सामने आते हैं, वही हमारी सारी दुनिया है, हमारे मेंटल होराइजन पर वही छाये हुए हैं। अधिकतर पॉलिटिकल लीडर्स इनके बारे में ही सोचते हैं और उनका मेंटल होराइजन इज कनफाइंड टू दिस क्लास आनली। गरीब, जो देहात में रहता है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। शायद आप यह समझते हैं कि गरीब देहात में है ही नहीं। उसका कोई जिक्र नहीं है। उसके बारे में आपके दिल में कोई दर्द नहीं है।

डिसइंट्रेस्टिड भाव से आप इस पर विचार करें। इलैक्शन जीतने की बात नहीं है। पचास—सौ गलत बातें कह कर इलैक्शन जीत कर आप आ सकते हैं।

आपने शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज की कंडीशंस को इम्प्रूव करने की बात कही है, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई डेफिनिट चीज भी उसमें नहीं है। केवल यही आपने कहा है कि जो स्कीम्ज हैं उनमें हम कोशिश करेंगे कि उनके लिए अलग से एलोकेशन हो जाए। कोई नई चीज नहीं है और नई चीज शायद हो भी नहीं सकती थी। मैं कहना चाहता हूँ कि वे जो हमारे भाई हैं, ये करीब 22 परसेंट हैं और उनमें से 17—18 परसेंट बिलो पॉवर्टी लाईन रहते हैं। इनके अलावा और भी 35—40 परसेंट हैं। उन सबके लिए भी आपको सोचना चाहिए। एक बार न्यूज आई थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच रही है शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज के लिए अलग इंतजाम करने की। वह आप करें। लेकिन सवाल बिलो पॉवर्टी लाइन वालों का है, चाहे वे इन जातियों से सम्बंध रखते हों या दूसरी जातियों से, शहरों में रहते हों या देहातों में; और मैं समझता हूँ कि उन सभी के लिए एक ही प्रोग्राम होना चाहिए और बहुत सोच—विचार करके उसको बनाया जाना चाहिए। मैं बाद में बताऊंगा कि नया इकोनॉमिक प्रोग्राम हो सकता है। इन सब को वह प्रोग्राम एम्ब्रेस क्यों न करे। कोई कंक्रीट प्रोजेक्ट्स आपने पेश नहीं किये हैं। अगर आप ईमानदारी से उनके लिए कुछ करना चाहते हैं और आपका इरादा है तो फिर 17—18 परसेंट जो ये हैं और 35—40 परसेंट दूसरे हैं, इनके अलावा, तो उनके लिए क्यों आप कुछ नहीं करते हैं।

गांवों का इसमें कोई जिक्र नहीं है। स्पीच के भाग बी के पैरा'ज 37 और 39 ही गांवों से ताल्लुक रखते हैं। अस्सी परसेंट आदमी वहीं रहते हैं, मास ऑफ दी पीपल वहीं हैं और मास ऑफ पॉवर्टी भी वहीं पर है। उनके लिए दो पैराज हैं। उनके वास्ते स्कीम्स आपने क्या बनाई हैं? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो स्कीम्स थीं उनके वास्ते आपने इस बजट में फाइनेंशियल एलोकेशन और भी कम कर दिया है। मार्जिनल फार्मर्स डेवलपमेंट स्कीम के वास्ते मेरे जमाने में 136 करोड़ रखा गया था, जबकि आपने 56 करोड़ कर दिया है। ड्राउट प्रोन एरियाज प्रोग्राम के वास्ते 3.59 करोड़ हुआ करता था, जिसको आपने 49 करोड़ कर दिया है। कमांड एरिया डेवलपमेंट ब्लाक्स के वास्ते 44 करोड़ था उसको आपने 15 करोड़ कर दिया है। एरिया प्लानिंग फार फुल एम्प्लायमेंट तो शायद उसमें नहीं आता है, उसमें तीन स्कीम्स थीं मार्जिनल और सब मार्जिनल किसानों के लिए। उसका एलोकेशन बजाए बढ़ाने के आपने घटाया। फिर जितने इसमें एग्रीकल्चरल वगैरह दूसरे इलैक्ट्रॉनिक्स और इलैक्ट्रिक कम्प्यूटर्स और हजार नाम जो आपने एग्जम्प्ट किये हैं, ऐसी किसानों की हजारों समस्याएं हैं। मसलन आज मुझे गैलरी में एक फ्रेंड मिले, आपकी पार्टी के हिमाचल प्रदेश के हैं, उन्होंने मुझे बताया, मैं पिछले साल हिमाचल गया था, वहां के मिनिस्टर और दूसरे लोगों ने भी बताया कि वहां पर सेब का दाम एक रुपया किलो है और दिल्ली में 5 रुपये के भाव पर कंज्यूमर को मिलता है। तो वह 4 रुपये कौन खाता है। गरीब को, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर को कुछ नहीं मिलता है। क्या उसकी कोई स्कीम आपके पास है? नहीं है। उसकी फिक्र किसी को नहीं है।

जमीन का जो इरोजन हो रहा है आपके जरिये, जो दोस्त मुझे कहते हैं, तो मैं तो निकम्मा हूँ ही, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ करके दिखाइये। इससे कुछ तसल्ली नहीं होनी चाहिए आपको कि मैंने यह नहीं किया। मैं जो प्रॉब्लम बता रहा हूँ वह यह है कि सॉयल कंजर्वेशन की बात है, जमीन इतनी खराब होती जा रही है कि आगे आने वाली जेनरेशन हमें कर्स करेगी। 4—5 प्लान में कितना रुपया सॉयल कंजर्वेशन के लिए लिया गया है? मेरे पास इस वक्त फिगर्स नहीं हैं, आप कहेंगे तो भेज दूंगा। जमीन पर सो तो सारा कुछ निर्भर करता है। एग्रीकल्चर मायने Utilisation of the existing soil resources लेकिन the conservation of the soil resources for the future generation.

क्या उसके लिए एक लफ्ज है ? नहीं है। राजस्थान का डेजर्ट नजफगढ़ एरिया में दिन—रात बढ़ता जा रहा है, डेजर्ट बढ़ता जा रहा है और शीप, गोट्स और जानवर जो उस जमीन में चरते हैं,

उनकी संख्या दुगुनी हो गई है। जब से स्वराज्य आया है उसका एरिया बढ़ता जा रहा है। Is there any word about it? Have you given any thought about that, I do not know? उसकी वजह यह है कि हमारी दुनिया तो दिल्ली तक ही है। यह पता नहीं कि आप कौन से जिले के रहने वाले हैं, अगर है तो वहां तक है।

एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ, दोस्तों से अर्ज करना चाहता हूँ कि गरीबी से बचने का जो रास्ता है वह शहर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के जरिये नहीं है। मेरे दास्तो, वह गांव और खेत के जरिये है। पॉवर्टी से बचने का जो एस्केप रूट है वह इंडस्ट्रियल सेक्टर में से निकल कर नहीं जायेगा कि पहले हम उसको बढ़ायें और बाद में देखा जायेगा। नहीं, पहले उस पर ध्यान दीजिये। जितना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन प्रति एकड़ बढ़ेगा with fewer and still fewer men on the soil. आदमी जितने कम होते जायेंगे, पैदावार फी एकड़ बढ़ती जायेगी। और जो रिलीफ वर्कर हैं, एग्रीकल्चरल हैं, वे इंडस्ट्री में शिफ्ट करेंगे, तब जाकर यह होगा। यह जो करने जा रहे हैं कि एक्सपोर्ट प्रमोशन से इंडस्ट्री बढ़ जायेगी, यह नहीं बढ़ेगी।

सन 51 की सेन्सस में 10 पर्सेन्ट आदमी इंडस्ट्री में थे, 9 इंडस्ट्री में थे— और एक माइनिंग में। सन 1961 में 10 पर्सेन्ट, एगजैक्टली द सेम रेशियो और 72 पर्सेन्ट एग्रीकल्चर में और '71 में भी ठीक वही रेशियो। मुल्क वही तरक्की किये माने जाते हैं, जहां एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन का पर्सेन्टेज घटता जाता है और नान-एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन का पर्सेन्टेज बढ़ता जाता है।

जब अंग्रेज आये थे, तो एक इकोनॉमिस्ट के हिसाब से 85 पर्सेन्ट आदमी खेती में लगा हुआ था और आज 72 पर्सेन्ट लगा हुआ है। उस समय 25, 30 पर्सेन्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री में लगे थे, डोमेस्टिक इंडस्ट्री सब बर्बाद हो गई अंग्रेज अपने कारखानों के हक में थे, कारखानों के माल से कॉटेज प्रोडक्ट कम्पीट नहीं कर सके। वह सब खत्म हो गये, बेरोजगार हो गये। 50 से 72 हुआ, मुल्क गरीब हुआ और अंग्रेज के जाने के बाद भी लिवरपूल या लंकाशायर की वजह से हमारा कॉटेज वीवर्स और आर्टिजन बेरोजगार हो गये। आज बिड़ला, टाटा और इंडस्ट्री हाउसेस बम्बई, कलकत्ता और अहमदाबाद में हैं, वही हमारे सामने प्रब्लम है। क्या फर्क पड़ा स्वराज्य का? आपका इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट कहां बढ़ा है?

शहर का यह हाल है कि एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में आज 1 करोड़ 50 लाख आदमी के नाम दर्ज हैं। अब से तीन साल पहले यह एक करोड़ 2 लाख थे। वह जनता पार्टी के जमाने में बढ़ते गये, क्योंकि जो हमारे मेंटल यूथ बन गये उनका छोड़ना आसान नहीं। हमारे दोस्तों का भी वही हाल था। माफ करें, पास तो कर लिया कि आगे नई इंडस्ट्री नहीं लगायेंगे उस काम को करने के लिए और उस चीज को पैदा करने के लिए जो कि छोटे पैमाने पर हो सकती है, but no thought was given to its implementation.

वही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमने आँखें मीच रखी हैं, शुतुर्मुख की तरह Unemployment can be washed away. मैं डीटेल्स को छोड़ देता हूँ। उसका एक ही इलाज है। कोई नहीं कहता है कि बड़ी फैक्ट्रीज न हों। उनके बिना देश का काम नहीं चल सकता है लेकिन जो फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स वह सामान पैदा करें, जो अपने मुल्क में छोटे पैमाने पर पैदा होता रहा था और आज हो सकता है, उनको आगे के लिए न लगने दीजिए। और जो आज लगी हुई वीविंग और स्पिनिंग में। वीविंग में सात लाख आदमी लगे हुए हैं। अगर हम कहें कि वीविंग मिलों का कपड़ा हिन्दुस्तान में नहीं बिकेगा, वह एक्सपोर्ट किया जाये और अगर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो वे बन्द हो जायें, लेकिन हिन्दुस्तान में अब हैण्डलूम प्रोडक्ट बिकेगा, तो इससे 84 लाख लड़कों को काम मिलता है। 12 आदमी हैण्डलूम पर उतना ही कपड़ा पैदा कर सकते हैं, जितना कि एक टैक्सटाइल वर्कर करता है। ऐसा करने में क्या मुसीबत है? इससे दो साल में सब मामले हल हो जायेंगे।

अगर मेरे दोस्त बुरा न मानें, तो मैं उन्हें एक मशवरा दूंगा कि वे अपने जिलों में 1880 के आस-पास के डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर पढ़ें, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की लाइब्रेरी में मिल सकते हैं। उसमें मिलेगा कि आपके जिले में फलां कस्बे में फलां कॉटेज इंडस्ट्री हुआ करती थी। आज वे नहीं हैं। कहां गये वे लोग? 1931 का सेन्सस रिपोर्ट उठा कर पढ़ें। उनमें से दो-तिहाई टुक टुक प्लो-वे खेती करने लगे। अंग्रेजों की फैक्ट्रियों के कॉम्पटीशन में वे खत्म हो गये। जो कुछ बचे होंगे, वे 1947 के बाद हमारे अपने इंडस्ट्रियल हाउसेज के कॉम्पटीशन की वजह से खत्म हो गये। अगर उन्हें प्रोटेक्शन दिया जायेगा, तो एम्प्लायमेंट बढ़ेगा।

इंदिरा जी यहां पर नहीं हैं। वाकया ऐसा हो गया है। इस इलेक्शन में मैंने अखबार में उनकी स्पीच पढ़ी कि वह अनएम्प्लायमेंट मिटाने के लिए हर एक परिवार को एक नौकरी देंगी। लेकिन नौकरी देने से अनएम्प्लायमेंट नहीं मिटेगा। 1972 में पटना ए0आई0सी0 में एक रिजोल्यूशन पास हुआ, जिसमें एग्जेक्टली यही कहा गया था कि हम पांच साल तक हर घर में एक लड़के को नौकरी देंगे, जिसे सौ रुपये मिलेंगे। यह न हो सका और न हो सकेगा।

अगर अनएम्प्लॉयमेंट मिटाना है, तो प्रॉडक्टिव एम्प्लॉयमेंट देना होगा, ताकि व्यक्ति को कुछ इन्कम भी हो और वह देश के प्रोडक्शन में इजाफा करे। उसकी परचेजिंग पावर हो। अगर हम अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ायें, मगर मार्सेज के पास परचेजिंग पावर न हो, तो वे सामान खरीद नहीं सकेंगे। वह समस्या हल होगी प्रॉडक्टिव एम्प्लॉयमेंट से। गांधी जी— जा कॉटेज इंडस्ट्री पर जोर देते थे, उनके बारे में कहा जाता है कि बूढ़ा आदमी हो गया है; दकियानूसी बात करता है, हमने बाहर का लिट्रेचर पढ़ा है, उसमें कॉटेज इंडस्ट्री का जिक्र नहीं है। लेकिन इसके अलावा कोई हल नहीं है। अगर कोई हल हो और कोई नौजवान कोई नया आइडिया दे सके— मेरी एज के बराबर तो शायद ही कोई हो, तो मैं उसके घर जाकर बहस करने के लिए तैयार हूँ। इसके अलावा इस समस्या का कोई इलाज नहीं है।

कॉटेज इंडस्ट्री तभी बढ़ेगी, जब बड़ी इंडस्ट्री पर लगाम लगे, क्योंकि कॉटेज इंडस्ट्री फिनांसली मैकेनाइज्ड इंडस्ट्री से कॉम्पीट नहीं कर सकेगी। लेकिन यह काम कौन करेगा? सब सेठ नाराज हो जायेंगे। मैं श्री वेंकटरामन की प्रब्लम को जानता हूँ। हिज पार्टी डिपेंडज ऑन दोज इंडस्ट्रियलिस्ट्स फॉर इट्स पॉलिटिकल सरवाइवल। अब आप यह इरादा कर लें कि अब तक तो हर इलेक्शन में आपने करोड़ों-करोड़ रुपये लिये हैं, लेकिन आगे नहीं लेंगे, तभी आप एक्शन ले सकेंगे, वर्ना एक्शन नहीं ले सकेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपने कथन को समाप्त करता हूँ। अगर मुझसे कोई ऐसी बात कही गई हो, जिससे श्री वेंकटरामन को तकलीफ हुई हो, अगर मैंने साफ न करने की कोशिश की है, तो वह मुझे माफ करें।

-----